पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

श्री प्रवीण आनंद

बनाम

भारत संघ एवं एक अन्य

2019 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1688

06 अगस्त 2024

(माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या डीआरटी को धोखाधड़ी/गलतबयान के आधार पर लोक अदालत द्वारा पारित किसी निर्णय को चुनौती देने या वापस लेने का अधिकार है?
- क्या डीआरटी द्वारा बार-बार दी गई रियायतें, पहले न माने गए समझौते के तहत भुगतान के लिए समय बढ़ाना, कानूनी रूप से मान्य थे?
- क्या अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से डीआरटी की कार्रवाई को चुनौती देना सही था?

हेडनोट्स

लोक अदालत के निर्णय - प्रकृति और चुनौती: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत लोक अदालतों द्वारा पारित निर्णय न्यायिक प्रकृति के नहीं होते, बल्कि आपसी समझौते और समझौते पर आधारित होते हैं। इन निर्णयों को केवल संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है, भले ही संदर्भित न्यायालय का वर्तमान पीठासीन अधिकारी लोक अदालत का सदस्य रहा हो।

लोक अदालत के निर्णयों की समीक्षा में डीआरटी का अधिकार क्षेत्र: ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) को लोक अदालत के निर्णयों की समीक्षा करने या उन्हें वापस लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, भले ही वह डीआरटी के भीतर या उसके अपने

पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, खासकर जब धोखाधड़ी या गलतबयानी का आरोप लगाया गया हो।

निपटान में गलतबयानी: जहाँ किसी निर्णय के गलतबयानी पर आधारित होने का दावा किया जाता है, वहाँ उचित उपाय उसे उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती देना है - डीआरटी के समक्ष विविध आवेदनों के माध्यम से नहीं।

लोक अदालत के निर्णयों की अंतिमता: लोक अदालत के निर्णयों की अंतिमता होनी चाहिए। यदि निपटान की शर्तों का सम्मान नहीं किया जाता है, तो आदेश स्वयं ही लागू हो जाता है। अनुपालन में विफलता के बाद डीआरटी द्वारा बाद में की गई रियायत अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

डीआरटी की समझौते की शर्तों को बढ़ाने में असमर्थता: एक बार समझौता न होने पर, संदर्भित न्यायालय या न्यायाधिकरण (जैसे डीआरटी) पदेन कार्यवाहक बन जाता है। वह दोनों पक्षों की सहमति के बिना आगे का समय नहीं दे सकता या शर्तों में एकतरफा बदलाव नहीं कर सकता।

न्याय दृष्टान्त

इंडियन बैंक्स बनाम ब्लू जैगर्स एस्टेट्स लिमिटेड एवं अन्य; **(2010) 8 एससीसी 129;** भार्गवी कंस्ट्रक्शन्स एवं अन्य बनाम कोथाकापु मुथ्यम रेड्डी एवं अन्य, **(2018) 13 एससीसी 480;** पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम जालौर सिंह एवं अन्य, **(2008) 2 एससीसी 660;** आर. जानकीअम्मल बनाम एस.के. कुमारस्वामी एवं अन्य, **(2021) 9 एससीसी 11;** डॉ. (श्रीमती) शशि प्रतीक बनाम चरण सिंह वर्मा एवं अन्य, **एआईआर 2009 एएलएल 109**

अधिनियमों की सूची

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993, भारतीय संविधान - अनुच्छेद 226 और 227, दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 -

आदेश XXIII नियम 3 और 3ए, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

मुख्य शब्दों की सूची

लोक अदालत, डीआरटी (ऋण वसूली न्यायाधिकरण), एसएआरएफएईएसआई, मिथ्याबयान, समझौता डिक्री, सहमति पंचाट

प्रकरण से उत्पन्न

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 19502/2016

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/अपीलकर्ता की ओर से: श्री अरबिंद कुमार झा, अधिवक्ता; श्री विजय कुमार वर्मा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/प्रतिवादियों की ओर से: श्री कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: रवि राज, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 19502

में

2019 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1688

==

श्री प्रवीण आनंद, पिता स्वर्गीय बलराम आनंद, पता- सी-71, 7वीं मंजिल, कृष्णा अपार्टमेंट, बोरिंग रोड, थाना- श्रीकृष्णा पुरी, पटना।

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, परिसम्पत्तियाँ वसूली शाखा, (एस.ए.आर.बी.), पटना, दूसरी मंजिल, एस.बी.आई. पटना मुख्य शाखा भवन, पश्चिम गांधी मैदान, पटना।

2. पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, विंग ए और बी, दूसरी मंजिल, कर्पूरी ठाकुर सदन, जी.पी.ओ.ए., राजीव नगर के पास, थाना- आशियाना दीघा रोड, पटना-800025 के माध्यम से भारत संघ।

.... उत्तरदाता/गण

==

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अरविंद कुमार झा, अधिवक्ता

श्री विजय कुमार वर्मा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

==

गणपूर्तिः माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

सी.ए.वी. निर्णय

(द्वाराः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक : 06-08-2024

रिट याचिकाकर्ता अपीलार्थी है, जो ऋण और दिवालियापन की वसूली अधिनियम, 1993 (इसके बाद 'आर.डी.बी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 19 (25) के तहत पारित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (इसके बाद 'डी.आर.टी.' के रूप में संदर्भित) के समक्ष लोक अदालत के आदेश के खिलाफ बैंक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के इनकार से व्यथित है। याचिकाकर्ता लोक अदालत में हुए समझौते के बाद उनके खिलाफ शुरू की गई वसूली की कार्यवाही से भी व्यथित था। लोक अदालत के आदेश को रिट याचिका में अनुलग्नक-7 के रूप में प्रस्तुत किया जाता है

और इसमें हस्तक्षेप करने वाले डी.आर.टी. के आदेश को अनुलग्नक-13 के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

2. विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि शुरू में 27 लाख रूपये का समझौता किया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा इसका पालन नहीं करने के बावजूद, डी.आर.टी. ने अपने समक्ष दायर विविध आवेदनों में, याचिकाकर्ता को और समय दिया था; जो अनुमेय नहीं था। डी. आर. टी. द्वारा दिया गया समय भी डी. आर. टी. के पहले के आदेशों के आधार पर, पहले से शुरू की गई वसूली कार्यवाही पर ध्यान दिए बिना था, जो रिट याचिकाकर्ता पर लोक अदालत के पहले के आदेश का पालन नहीं करने पर पारित किया गया था। विविध आवेदन में ऐसे आदेशों में से अंतिम, जिसने याचिकाकर्ता को और समय दिया था, अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित था। डी. आर. टी. द्वारा पहले से जारी वसूली का प्रमाण पत्र अभी भी वैध था। रिट याचिका में आरोपित लोक अदालत का आदेश स्पष्ट रूप से गलत तरीके से प्रस्तुत करने का मामला था, जिसमें बैंक का बकाया 96,134/- रूपये के रूप में दर्ज किया गया था, जबकि वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार कुल बकाया राशि 30.11.2014 को 52,07,624/- रूपये थी।

3. डी. आर. टी. द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों पर भी गौर किया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि चूंकि विवादित पंचाट तथ्यों की गलत प्रस्तुति पर पारित किया गया था; जो आधार रिट याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णयों में मौजूद नहीं था, डी. आर. टी. पंचाट में हस्तक्षेप करने के लिए पूरी तरह से अपने अधिकार क्षेत्र में था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि ***भारतीय बैंक बनाम ब्लू जैगर्स एस्टेट्स लिमिटेड और अन्य; (2010) 8 एस. सी. सी. 129*** में निर्णय पूरी तरह से वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए लागू हुआ। यद्यपि, बैंक के एक अधिकारी द्वारा समझौता किया गया है; बैंक सार्वजनिक धन का संरक्षक है, तथा यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका है कि समझौता तथ्यों की गलत प्रस्तुति पर आधारित है,

फिर भी लोक अदालत के आदेश के विरुद्ध बैंक द्वारा डीआरटी में जाना पूरी तरह से उचित था, ऐसा निष्कर्ष दिया गया।

4. हमारे समक्ष, अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता ने ***भार्गवी कंस्ट्रक्शंस एवं एक अन्य बनाम कोठाकापु मुथियम रेड्डी और अन्य; (2018) 13 एससीसी 480*** पर निर्भरता रखी गई। ***पंजाब राज्य और एक अन्य बनाम जालौर सिंह और अन्य; (2008) 2 एस. सी. सी. 660,*** में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था कि लोक अदालत के आदेश को चुनौती केवल अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष दी जा सकती है। यह तर्क दिया जाता है कि आक्षेपित आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है।

5. प्रत्यर्थी-बैंक की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने, हालांकि, जोर देकर कहा कि जब धोखाधड़ी और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया जाता है, तो यह लोक अदालत के समक्ष हुए समझौते को दूषित करता है। प्रत्यर्थी-बैंक का अधिकारी किसी कारण से; शायद तथ्यों से पूरी तरह से अवगत नहीं होने पर, निपटान के लिए सहमत हो गया, एक छोटी राशि के लिए जब पहले से ही भारी राशि के लिए वसूली प्रमाण पत्र रिट याचिकाकर्ता-उधारकर्ता के खिलाफ वसूली लंबित थी। ***आर. जानकीम्मल बनाम एस. के. कुमारसामी और अन्य; (2021) 9 एस. सी. सी. 114*** पर यह तर्क देने के लिए भरोसा रखा गया था कि समझौता डिक्री यदि कथित रूप से शून्य या शून्यकरणीय है, तो उक्त सहमति डिक्री के एक पक्ष को उसे चुनौती देने के लिए, उसी अदालत से संपर्क करना होगा, जिसने समझौते को दर्ज किया था। डी. आर. टी. ने लोक अदालत में समझौते को दर्ज किया था और यह पूरी तरह से ठीक था कि बैंक ने समझौते के खिलाफ डी. आर. टी. से संपर्क किया था।

6. शुरुआत में, हमें यह देखना होगा कि अपीलकर्ता, उधारकर्ता का आचरण संदिग्ध है, क्योंकि पहले के लोक अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया था और फिर

लोक अदालत में किए गए समझौते का पालन करने के लिए समय बढ़ाने के लिए कई बार न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया गया था। हालाँकि, कानूनी मुद्दों, विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र या इसकी कमी, का निर्णय केवल उधारकर्ता के संदिग्ध आचरण या इस साधारण सिद्धांत के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है कि बैंक सार्वजनिक धन के साथ व्यवहार करते हैं और न्यायालय विशुद्ध रूप से तकनीकी मुद्दों पर बेईमान चूककर्ता उधारकर्ताओं से ऐसे सार्वजनिक धन की वसूली के लिए शुरू की गई कानूनी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम करेंगे।

7. हमें डी. आर. टी. के समक्ष कार्यवाही के विस्तृत विवादास्पद इतिहास का विवरण देना होगा। बैंक ने शुरू में ब्याज और लागत के साथ 34,01,934.21 रूपये की राशि की प्राप्ति के लिए डी. आर. टी., पटना के समक्ष 2008 का मूल आवेदन सं. 24 दाखिल किया था। डी. आर. टी. में गठित एक विशेष लोक अदालत में, अनुलग्नक-1 द्वारा, ऋण राशि की संतुष्टि के लिए एक समझौता किया गया था, जिसमें किस्तों में 27 लाख रूपये का भुगतान किया गया था; आदेश में ही निर्दिष्ट तिथि-वार, जिसमें से अंतिम किश्तें 17.01.2011 को आई थीं। याचिकाकर्ता लोक अदालत के आदेश के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहा और डी. आर. टी. मूल आवेदन (ओ.ए.) दायर करने के साथ आगे बढ़ा, कार्यवाही जिसमें 01.02.2008 से संविदात्मक दर पर लंबित मामले और भविष्य के ब्याज के साथ, मांगी गई राशि की वसूली के प्रमाण पत्र में समाप्त हुई, जारी किया जा रहा है (रिट याचिका का अनुलग्नक-2)।

8. बैंक ने वसूली अधिकारी, डी. आर. टी., पटना के समक्ष 2011 का आर. पी. मामला सं. 40 भी शुरू किया और उक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, विशेष लोक अदालत के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, डी. आर. टी., पटना के समक्ष वसूली पर रोक लगाने के लिए 2012 का एम.ए. सं. 79 दायर किया गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया गया था, डी. आर. टी. द्वारा एक नया निर्देश जारी किया गया

था कि याचिकाकर्ता निपटान राशि का 40 प्रतिशत 15 दिनों के भीतर और शेष राशि का 3 महीने में समान किश्तों में भुगतान करेगा, साधारण प्रधान ऋण दर (पी.एल.आर.) ब्याज के साथ; जो आदेश रिट आवेदन के अनुलग्नक-3 के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। डी. आर. टी. के पास समझौते के आधार पर ऐसा समय देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था; जो समझौते को तारीख-वार विशिष्ट किश्तों के साथ सुरक्षित किया गया था; जिसका पालन नहीं किया गया तो समझौता ही समाप्त हो जाएगा और विशेष लोक अदालत के फैसले का कोई परिणाम नहीं होगा। जो भी हो, बैंक ने उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी और उधारकर्ता डी. आर. टी. द्वारा दिए गए अगले समय में भी निपटान राशि को पूरा करने में विफल रहा।

9. इस प्रकार, वसूली अधिकारी 2011 के आर. पी. मामला सं. 40 के साथ आगे बढ़े और बंधक संपत्तियों की नीलामी बिक्री को अधिसूचित किया गया। एक बार फिर, डी. आर. टी. के समक्ष किश्तों में निपटान राशि का भुगतान करने के लिए और समय की प्रार्थना करते हुए 8 लाख रुपये के चेक के साथ विविध अपील दाखिल किया गया। डी. आर. टी. ने एक बार फिर अपने दिनांक 19.07.2012 के आदेश द्वारा वसूली को स्थगित कर दिया और उधारकर्ता को चूक की तारीख से 9 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ लोक अदालत के समक्ष 17.01.2010 के समझौते के अनुसार शेष राशि का भुगतान करने का अंतिम मौका दिया गया। न्यायाधिकरण द्वारा राशियों के निपटान के लिए दो महीने का समय दिया गया था; जिसका फिर से अपीलार्थी/उधारकर्ता द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था।

10. फिर भी, 2005 का विविध अपील सं. 378 अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया था जिसमें 2010 में विशेष लोक अदालत के आदेश का फिर से उल्लेख करते हुए एक आदेश 04.04.2014 को पारित किया गया था और समझौते के अनुसार राशि का भुगतान करने के लिए तीन मासिक किश्तों की अनुमति दी गई थी और अपीलार्थी/आवेदक को न्यायाधिकरण से संपर्क करने की अनुमति दी गई थी, यदि शेष राशि का भुगतान करने में कोई समस्या आती है; समझौता राशि को कम करने के लिए। हम यह देखे बिना नहीं रह

सकते कि ये दोहराए जाने वाले आदेश स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना थे। अंतिम आदेश को प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डी. आर. ए. टी.) के समक्ष चुनौती दी गई है जिसमें कार्यवाही 2014 के एस. आर. सं. 135 के रूप में पंजीकृत है।

11. अपीलार्थी का दावा है कि उसने दिनांकित 04.04.2014 के आदेश के अनुसार पर्याप्त भुगतान किया था, और इसके कारण विशेष लोक अदालत के समक्ष बैंक का बयान आया कि जो भुगतान किया जाना बाकी है वह केवल 96,134/- रूपये है और 20,000/- रूपये के भुगतान द्वारा दावे को निपटाने के लिए एक समझौता किया गया था; जिसे अपीलार्थी द्वारा भुगतान कर दिया गया है। लोक अदालत द्वारा 2015 के विविध अपील सं. 51 के माध्यम से पारित पंचाट को चुनौती दी गई जिसमें आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

12. हमें पहले अपने समक्ष रखे गए निर्णयों से निपटना होगा ताकि किसी समझौते की डिक्री को चुनौती देने के अधिकार क्षेत्र को समझा जा सके; जो हमें देखना होगा कि कानून के न्यायालय के समक्ष पक्षों के बीच किए गए समझौते में प्राप्त एक समझौते की डिक्री के रूप में विशिष्ट और अलग हैं, विशेष रूप से दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत और एक समझौते के परिणामस्वरूप कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (इसके बाद 'एलएसए अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत गठित लोक अदालत द्वारा पारित एक निर्णय।

13. ***आर. जानकीम्मल (उपरोक्त),*** एक मामला था जो पारिवारिक और व्यक्तिगत कानूनों के तहत उत्पन्न हो रहा था। जो विभाजन, पारिवारिक व्यवस्थाओं और समझौतों और परिवार और उसके सदस्यों द्वारा धारण की गई संपत्तियों की स्थिति से संबंधित थे, चाहे वह संयुक्त रूप से आयोजित की गई हो या स्वयं अर्जित की गई हो। प्रत्यर्थी-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस प्रश्न से निपटा गया और उस पर प्रकाश डाला गया, वह इस आधार पर एक समझौता डिक्री को चुनौती देने के लिए मंच

के बारे में था कि यह गैरकानूनी था। दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII नियम 3 ए को ध्यान में रखते हुए, जो इस आधार पर डिक्री को दरकिनार करने के लिए एक मुकदमे को रोकता है किया गया समझौता वैध नही था, आदेश XXIII नियम 3 ए में 'वैध' शब्द नियम 3 के स्पष्टीकरण के साथ जोड़ा गया था जिसमें घोषणा की गई है कि एक व्यवस्था या समझौता जो भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत शून्य या शून्यकरणीय है, उसे विधिसम्मत नहीं माना जाएगा। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कोई करार या समझौता, यदि स्पष्ट रूप से शून्य या शून्यकरणीय है, तो विधिसम्मत नहीं होगा और आदेश XXIII नियम 3 ए के तहत प्रतिबंध को आकर्षित करेगा और शून्य या शून्यकरणीय डिक्री को दरकिनार करने के लिए एक अलग मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है; लेकिन समझौता करने वाला पक्ष उस न्यायालय के समक्ष सवाल कर सकता है जिसने विवादास्पद समझौता दर्ज किया था और वह न्यायालय जिसने डिक्री पारित की थी, इस विवाद का फैसला करने के लिए आदेश दिया गया है कि क्या पक्ष आए हैं और कानूनी तरीके से मुकदमे को समायोजित किया है।

14. एक बार फिर, हमें दी.प्र.सं के तहत समझौते पर पारित डिक्री और एल. एस. ए. अधिनियम के तहत पारित पंचाट की विशिष्ट प्रकृति और स्थिति को दोहराना होगा। निर्णय लिया जाने वाला प्रश्न यह होगा कि डी. आर. टी. या किसी अन्य न्यायालय में लोक अदालत का गठन कब किया जाता है; क्या लोक अदालत का गठन करने वाले सदस्य अपने साथ न्यायालयों का दर्जा लाएंगे, जो वे आम तौर पर कब्जा कर रहे हैं और पारित किए गए पंचाट को भी प्रदान करते हैं, उस न्यायालय द्वारा पारित किए गए पंचाट/डिक्री का दर्जा जिस पर वे आधिकारिक रूप से कब्जा करते हैं। यदि उत्तर नकारात्मक है, तो लोक अदालत के निर्णय को न्यायालय में चुनौती देने का कोई सवाल ही नहीं है, आमतौर पर सदस्य/सदस्यों द्वारा कब्जा किया गया। ***आर. जानकीम्मल (उपरोक्त)*** में निर्णय का एल. एस. ए. अधिनियम के तहत पारित पंचाटों के रूप में बिल्कुल कोई अनुप्रयोग नहीं है।

15. इस संदर्भ में, ***पंजाब राज्य बनाम जालौर सिंह (उपरोक्त)*** में तीन न्यायाधीशों की पीठ प्रासंगिक है। इसमें लोक अदालत का पंचाट मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश से मोटर दुर्घटना दावे में मुआवजे के संबंध में था जो एक अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था। अपील को निपटारे के लिए उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लोक अदालत में भेजा गया था और जब मामला उठाया गया था, तो पक्षकार मौजूद नहीं थे, लेकिन वकील मौजूद थे। लोक अदालत ने मुआवजे को बढ़ाने का आदेश पारित किया और यह भी प्रावधान किया कि यदि पक्षकार वृद्धि पर आपत्ति करते हैं, तो वे अपील के निपटारे के लिए दो महीने के भीतर उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। अपीलार्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पंचाट को चुनौती दी और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उस निष्कर्ष को खारिज कर दिया कि यह बनाए रखने योग्य नहीं था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अनुच्छेद 226 या 227 के तहत रिट याचिका पर निर्णय लेने में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर जोर दिया और पुष्टि की और जिस तरह से पूरे मामले से लोक अदालत का उद्देश्य और उद्देश्य को कम करते हुए निपटाया गया, उस पर निराशा व्यक्त की। लोक अदालत के निर्णय के संदर्भ में, पक्षकारों द्वारा सहमत नहीं होने पर, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने का विकल्प उच्च न्यायालय के पास था, यह निष्कर्ष था।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने लोक अदालतों के निर्णयों/पंचाटों को चुनौती देने के तरीके को विस्तार से बताया; जिसे इस मामले में आक्षेपित निर्णय में शामिल नहीं किया गया। एल.एस.ए. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक लोक अदालत के पास किसी भी लंबित मामले के संबंध में पक्षकारों के बीच समझौता या करार करने का अधिकार क्षेत्र होगा, जिसके लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और यहां तक कि मुकदमेबाजी से पहले के

मामलों में भी; लेकिन उनके पास कोई न्यायनिर्णायक या न्यायिक कार्य नहीं हैं और उनका कार्य विशुद्ध रूप से और केवल सुलह का है।

17. हम विशेष रूप से ***जालौर सिंह (उपरोक्त)*** के कंडिका 8 और 9 का उल्लेख करते हैं, जो यहां निकाले गए हैंः-

> **8.** उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि लोक अदालतों का कोई न्यायनिर्णायक या न्यायिक कार्य नहीं है। उनके कार्य विशुद्ध रूप से सुलह से संबंधित हैं। एक लोक अदालत पक्षकारों के बीच एक समझौते या करार के आधार पर एक संदर्भ निर्धारित करती है, और समझौते या करार के संदर्भ में एक पंचाट देकर अपनी पुष्टि की मुहर लगाती है। जब लोक अदालत किसी समझौते या करार पर पहुंचने में सक्षम नहीं होती है, तो कोई पंचाट नहीं दिया जाता है और कानून के अनुसार निपटान के लिए, मामले का अभिलेख उस अदालत को वापस कर दिया जाता है जिससे संदर्भ प्राप्त हुआ था। अदालत की तरह किसी भी लोक अदालत के पास मामलों में निर्णय लेने के लिए पक्षों को "सुनने" की शक्ति नहीं है। यह पक्षकारों के साथ विषय-वस्तु पर चर्चा करता है और उन्हें एक न्यायपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए राजी करता है। अपनी सुलहकारी भूमिका में, लोक अदालतें न्याय, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती हैं। जब एल. एस. ए. अधिनियम लोक अदालत द्वारा "निर्धारण" और लोक अदालत द्वारा "पंचाट" का उल्लेख करता है, तो उक्त अधिनियम न तो न्यायिक निर्धारण पर विचार करता है और न ही न्यायिक निर्धारण की आवश्यकता है, बल्कि लोक अदालत के मार्गदर्शन और सहायता के साथ पक्षों द्वारा किए गए समझौते या करार के आधार पर एक गैर-न्यायिक निर्धारण है। लोक अदालत के "पंचाट" का अर्थ

किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कोई स्वतंत्र निर्णय या राय नहीं है। पंचाट देना केवल लोक अदालत की उपस्थिति में पक्षों द्वारा सहमत समझौते या करारों की शर्तों को लोक अदालत के हस्ताक्षर और मुहर के तहत निष्पादन योग्य आदेश के रूप में शामिल करने का एक प्रशासनिक कार्य है।

9. लेकिन हम पाते हैं कि कई मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सदस्यों के रूप में लोक अदालतों में भाग लेते हुए, अदालतों की तरह, पक्षों को सुनकर और पक्षकारों पर न्यायसंगत और समतामूलक होने के बारे में अपने विचार थोपकर लोक अदालतों का संचालन करते हैं। कभी-कभी वे बहक जाते हैं और गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इस मामले में, भले ही कोई सर्वसम्मति या समझौता न हो। इस तरह के कार्य, लोक अदालतों के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने के बजाय, वादियों को लोक अदालतों से दूर कर देंगे। लोक अदालतों को न्यायाधीशों की भूमिका निभाने के उनके प्रलोभन का विरोध करना चाहिए और सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। लोक अदालतों का प्रयत्न और प्रयास न्याय, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के संदर्भ में पक्षों को उनके संबंधित दावों के पक्ष और विपक्ष, ताकत और कमजोरियों, फायदे और नुकसान को समझाकर विवाद को निपटाने के लिए मार्गदर्शन और राजी करना होना चाहिए।

18. हम लोक अदालत का गठन करने वाले सदस्यों के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त सावधानी पर जोर देते हैं; चाहे वह मौजूदा हो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अदालतों की तरह लोक अदालत में पक्षकारों की सुनवाई करके और अपने

विचारों को लागू करके कार्यवाही में भाग लेते हैं और उनका संचालन करते हैं, जिसे वे न्यायसंगत और समतापूर्ण मानते हैं। लोक अदालतें न्यायाधीशों की भूमिका नहीं निभाती हैं और उस संदर्भ में, उस न्यायालय में पंचाट को चुनौती देने का कोई सवाल ही नहीं है जिसमें आम तौर पर लोक अदालत का सदस्य बैठता है। हम इस तथ्य पर भी जोर देते हैं कि अक्सर लोक अदालतों का गठन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से किया जाता है, जिस स्थिति में पारित पंचाट को चुनौती देने के लिए कोई अदालत मौजूद नहीं होगी। बार के सदस्यों के साथ गठित लोक अदालतें भी होंगी जिन्हें फिर से ऐसे सदस्य के कब्जे वाले न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है; जो अस्तित्व में नहीं है। केवल इसलिए कि एक वर्तमान न्यायिक अधिकारी लोक अदालत या लोक अदालत का सदस्य है, जो लोक अदालत में पारित पंचाट को चुनौती देने के लिए न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा, जो वह आम तौर पर रखता है। न ही लोक अदालत के किसी निर्णय को उस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है जिसने इसे भेजा था, क्योंकि एक बार मामला भेजे जाने और मामले का निपटारा हो जाने के बाद, संदर्भ न्यायालय कार्यात्मक अधिकारी बन जाता है। लोक अदालतों में मुकदमेबाजी से पहले के मामले भी सुलझाए जाते हैं जिन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा संदर्भित नहीं किया जाता है। यही कारण है कि हमने शुरुआत में इस बात पर जोर दिया कि दी.प्र.सं. के तहत पारित एक समझौता डिक्री और एल.एस.ए. अधिनियम के तहत गठित, लोक अदालतों के समक्ष किए गए समझौते के आधार पर एक पंचाट के रूप में एक अंतर है।

19. ***भार्गवी निर्माण (उपरोक्त)*** में सर्वोच्च न्यायालय के बाद के निर्णय ने **जालौर सिंह (उपरोक्त)** में तीन न्यायाधीशों की पीठ का अनुसरण किया और स्पष्ट रूप से लोक अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए एक विशेष उपाय निर्धारित किया गया है, जिसका प्रत्येक वादी को अक्षरशः और भावना से पालन करना होगा, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कानून होने के नाते माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की

गई घोषणा जैसा कि ***एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ; (2006) 8 एससीसी 212*** में निर्धारित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई कानून की घोषणा के आधार पर मामले की जांच करते हुए, हम अपने दिमाग में स्पष्ट हैं कि 2015 के विविध अपील सं. 51 द्वारा डी.आर.टी. के समक्ष, बैंक द्वारा पंचाट को दी गई चुनौती स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस तथ्य के बावजूद कि डी. आर. टी. का पीठासीन अधिकारी लोक अदालत था जिसने पंचाट पारित किया था। न तो यह बात और न ही यह तथ्य कि मामला डी. आर. टी. द्वारा लोक अदालत को भेजा गया था, डी. आर. टी. को समझौते पर पारित पंचाट की शुद्धता या अन्यथा की जांच करने का अधिकार के साथ सशक्त नहीं बनाता है। न ही यह इस मुद्दे की जांच कर सकता है कि क्या यह धोखाधड़ी या गलत निरूपण पर पारित किया गया है; ये आधार केवल तभी उठाए जा सकते हैं जब उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में पारित पंचाट को उचित चुनौती दी जाए।

20. हमने शुरुआत में यह भी देखा कि हम केवल पार्टियों के आचरण पर या सार्वजनिक धन की रक्षा के लिए हमारी चिंता के आधार पर, अधिकार क्षेत्र के मामलों पर निर्णय लेने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते विद्वान एकल न्यायाधीश ने ***इंडियन बैंक (उपरोक्त)*** में निर्णय और न्यायाधिकरण द्वारा संदर्भित ***डॉ. (श्रीमती) शशि प्रतीक बनाम चरण सिंह वर्मा और दूसरा; ए. आई. आर. 2009 आल 109*** में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दिया है। उचित सम्मान के साथ, हमें ध्यान देना होगा कि ***इंडियन बैंक और शशि प्रतीक (दोनों उपरोक्त)*** के निर्णय के कंडिका को आक्षेपित निर्णय के कंडिका 24 में एक साथ निकाले गए थे; जो यह धारणा देता है कि बाद के कंडिका में तय किया गया अधिकार क्षेत्र का मुद्दा, पूर्व कंडिका में बताए गए सिद्धांत का परिणाम था; जो कि यह नहीं है। **इंडियन बैंक (उपरोक्त)** में निर्णय के पहले कंडिका में बैंकों के सार्वजनिक धन के न्यासी होने के पहलू पर जोर दिया गया है, जिसमें एल. एस. ए. अधिनियम के तहत किसी पंचाट पर विचार नहीं किया गया था। डी. आर. टी. द्वारा निकाले गए कंडिका में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के

फैसले से, न्यायाधिकरण को धोखाधड़ी या गलत निरूपण या तथ्य की गलती के आधार पर लोक अदालत द्वारा पारित आदेश या पंचाट को सशक्त बनाने या वापस लेने का हकदार पाया गया; जो स्पष्ट रूप से ***जालौर सिंह (उपरोक्त)*** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है। ***इंडियन बैंक (उपरोक्त)*** सी.पी.सी. या एल.एस.ए. अधिनियम के तहत एक समझौता डिक्री के खिलाफ चुनौती के मुद्दे से नहीं निपटता है, और उसमें वर्णित सिद्धांत, हालांकि सार्वभौमिक अनुप्रयोग है; लोक अदालत द्वारा पारित एक पंचाट को चुनौती देने के तरीके के संबंध में क्षेत्राधिकार के मुद्दे को असंगत नहीं बना सकता है, जैसा कि इससे पहले पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार किया गया था।

21. हम रिट याचिका में चुनौती दिए गए अनुलग्नक-13 में आदेश को बनाए रखने का कोई कारण नहीं पाते हैं। हम विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट देते हैं और अनुलग्नक-13 के आदेश को दरकिनार कर देते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि बैंक को अनुच्छेद 226 के तहत एक उचित रूप से स्थापित रिट याचिका में पंचाट को चुनौती देने का उपाय छोड़ दिया जाएगा। बैंक इस निर्णय को अपलोड करने की तारीख से 3 महीने के भीतर ऐसी कार्यवाही शुरू करेगा, यदि वह ऐसा करना चाहता है। इस बीच, बैंक को उन दस्तावेजों को सौंपने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिनके द्वारा उधारकर्ता/अपीलार्थी ने संपार्श्विक प्रतिभूति प्रदान करते हुए संपत्तियों का बंधक बनाया। बैंक डी. आर. टी. के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर मुकदमा चलाने का भी हकदार होगा, जिसने अनुलग्नक-1 द्वारा किए गए समझौते के अनुसार ऋण राशि का भुगतान करने के लिए और समय दिया; जब उधारकर्ता अनुलग्नक-1 का पालन करने में विफल रहा और अनुलग्नक-1 के अनुसार ऋण राशि का भुगतान करने के लिए डी. आर. टी. द्वारा दिखाए गए दो बाद के भोग का पालन करने में भी विफल रहा; जैसा कि हमने माना है, ये सभी अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और एल. एस. ए. अधिनियम के तहत निहित सिद्धांतों के खिलाफ काम करते है।

22. न्यायिक निर्णय के रूप में, लोक अदालत द्वारा पारित पंचाटों की भी अंतिमता होनी चाहिए। यदि समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो अनिवार्य रूप से समझौते पर आधारित आदेश अपने आप काम करता है और न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित आगे का समझौता नहीं हो सकता है, जिसने मामले को लोक अदालत को भेजा है, विशेष रूप से दूसरे पक्ष की सहमति के बिना।

23. अपील की अनुमति है लेकिन उपरोक्त आपत्तियों और प्रतिवादी-बैंक को दी गई स्वतंत्रता के साथ। पक्षों को अपनी-अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

पार्थ सारथी, न्यायमूर्तिः मैं सहमत हूँ।

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

शारुन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।